भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1766

बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना

1766 # डा. भीम सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय के अंतर्गत पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत किस प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है;
- (ख) पैक्स के माध्यम से विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर में किस प्रकार के मॉड्यूल उपलब्ध हैं;
- (ग) यह सॉफ्टवेयर पैक्स के कार्यों में पारदर्शिता लाने में किस प्रकार सहायक होगा; और
- (घ) इससे किसानों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कामन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है। अब तक, 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र से 67,930 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिसके लिए संबंधित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 654.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर के कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास नाबार्ड द्वारा किया गया है और 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 25,674 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है।

पैक्स की व्यवहार्यता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर उन्हें जीवंत आर्थिक संस्थान बनाने हेतु उनके व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स हेतु आदर्श उपविधियां तैयार कर दिनांक 5 जनवरी, 2023 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुरूप उनमें यथोचित बदलाव करने के उपरांत PACS द्वारा अपनाने के लिए परिचालित किए गए हैं। ये उपविधियां PACS को डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों की स्थापना; खाद्यान्न, उर्वरकों, बीजों के प्रापण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रिब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक

ऋण, कस्टम हाइरिंग केंद्र, कॉमन सेवा केंद्र, उचित मूल्य की दुकानों (FPS), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय अभिकर्ता कार्य, आदि सहित 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे। इन आदर्श उपविधियों को अपना कर पैक्स बहुसेवा केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान कर सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। आदर्श उपविधियां PACS के प्रचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने में सहायक होंगी; किसान सदस्यों को कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं प्रदान करेंगी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेंगी।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण की परियोजना का लक्ष्य पैक्स के आदर्श उपविधियों में विनिर्दिष्ट 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलापों के लिए एक व्यापक ERP सॉल्यूशन प्रदान करना है जिसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण के लिए वित्तीय सेवाएं, प्रापण प्रचालन, सार्वजनिक वितरण की दुकानों (PDS) का प्रचालन, व्यवसाय योजना, भंडारण, क्रय-विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, आदि जैसे विभिन्न मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।

(ग): ERP (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से PACS के प्रदर्शन में दक्षता लाता है। इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है जिससे ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (STCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है। इससे पैक्स के कार्यकरण के प्रति किसानों के बीच विश्वसनीयता बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में यह अपना योगदान देगा।

(घ): लगभग 1.05 लाख पैक्स से 13 करोड़ से भी अधिक किसान सदस्य जुड़े हैं। यह परियोजना किसानों की अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाती है। पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना पैक्स की आदर्श उपविधियों के अंतर्गत उल्लिखित विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों हेतु विभिन्न मॉड्यूलों को शामिल करके किसानों को पैक्स स्तर पर ही इन सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब, पैक्स को देश भर में ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि सेवाओं, आदि सहित 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम किया गया है। इस प्रकार, यह पैक्स के आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण में मदद करता है, जिससे किसान सदस्यों को आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत प्राप्त करने में सक्षम करता है।